ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, *RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14, Vol.-I, No.-1,* **PP-145-147**, *YEAR 2014*

वैश्वीकरण और भारत

❑ डॉ0 रूदल कुमार सिंह*

वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। आज सम्पूर्ण विश्व में वैश्वीकरण को अपनाया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस इत्यादि जैसे राष्ट्र भी वैश्वीकरण को अपना चुके है। वैश्वीकरण की शुरूआत ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (*IMF, WORD BANK, GATT*) की स्थापना के साथ हुई। परन्तु वैश्वीकरण का सम्पूर्ण विश्व में विस्तार सोवियत संघ के विघटन और विश्व में पूँजीवाद फैलाव तथा 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन (*W.T.O.*) की स्थापना के साथ हुआ। इसके चार पहलू है– वस्तुओं एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह, पूँजी का मुक्त प्रवाह, सूचना का मुक्त प्रवाह एवं श्रम का मुक्त प्रवाह।

वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो अनिवार्यतः बहुलवादी है। इस प्रक्रिया ने नये प्रकार के साम्राज्यवाद को जन्म दिया है। आज पूरे विश्व का परिदृश्य तेजी से परिवर्तित हो रहा है। वैश्विक वातावरण इस तरह का निर्मित होता जा रहा है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा एवं अस्तित्व बनाए रखने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर आने को तैयार है। वैश्वीकरण का एक पहलू वस्तुओं एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह है। भारत जैसे राष्ट्रों में आयात शुल्क वैश्वीकरण के फलस्वरूप 100 से घटकर मात्र लगभग 10ः रह गया है। वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का जाल फैलता जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विकासशील देशों पर अनावश्यक दबाव डालकर विकासशील देशों को नुकसान पहुँचा रही है। विकासशील देशों में विकसित देशों की संस्कृति का प्रसार किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टि से सम्पन्न विकसित देश संचार उपकरणों द्वारा अपनी जीवन शैली और संस्कृति को विकासशील देशों पर थोप रहे है ताकि विकसित देश अपने दैनिक उत्पाद विकासशील देशों में आसानी से बेच सके। वैश्वीकरण के नाम पर विकसित देश, वस्तुओं, सेवाओं एवं पूँजी के मुक्त प्रवाह का समर्थन तो कर रहे है परन्तु श्रम के मुक्त प्रवाह का विरोध कर रहे है। विकासशील देशों से आने वाले श्रम पर प्रतिबन्ध लगा रहे है।

भारत को आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत अपने प्राचीन एवं मान्य मानदण्डों तथा वैश्वीकरण–जनित नवीन किन्तु खण्डित मानदण्डों और चकाचौंध के मध्य फँसती जा रही है। जीवन मूल्य में अनास्था का विस्तार हुआ है, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का मौलिक दृष्टिकोण बदल रहा है। राज्य का कल्याणकारी दृष्टिकोण आमजन के कल्याण के स्थान पर उच्चवर्गीय सामाजिक संरचना और तकनीकी अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित होता जा रहा है। राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई विश्व व्यापारीकरण की प्रक्रिया ने आर्थिक उदारवाद की प्रक्रिया के विकास के साथ 'विश्व नागरिक' की अवधारणा को जन्म दिया है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण भारत में व्यापक पूँजी निवेश, कुशल श्रम, किन्तु विखण्डित संस्कृति का प्रसार हो रहा है। अकुशल श्रम और छोटे निवेशक जड़ता के शिकार हो रहे है। एक तरफ भारत में औद्योगिक विकास, नगरीकरण तथा तकनीकी ज्ञान बढ़ा है तो दूसरी तरफ निर्धनता भी बढ़ी है। असंगठित श्रम व्यावहारिक श्रम कानूनों का लाभ नहीं ले पा रही है। वैश्वीकरण के प्रभाव से शिक्षा का क्षेत्र भी अछुता नहीं

*प्रवक्ता–राजनीति विज्ञान किसान पी0जी0 कालेज रक्सा–रतसड़, बलिया, उ0प्र0

है। शिक्षा विज्ञान, तकनीक तथा वास्तविकताओं के निकट पहुँच रही है और सूचना का समुच्चय बनती जा रही है। वैश्वीकरण के कारण शिक्षा सामान्यीकरण से विशिष्टीकरण की तरफ बढ़ रही है।

वैश्वीकरण भारत की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन–बिन्दु है। 1991 ई0 में भारत ने तत्कालीन परिस्थितियों से विवश होकर स्वयं को वैश्विक अर्थ व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय किया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से जुड़ने को लेकर भारत ने राज्यों एवं राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं थी। इकाई राज्यों की माँग थी की वैश्वीकरण की प्रक्रिया हमारे संघीय ढाचे को प्रभावित करेगी, जिससे राज्यों की शक्तियाँ कम होगी। अतः ऐसे किसी भी निर्णय को राज्यों की सहमति के बिना क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए। कृषि एवं व्यापार सम्बन्धी मुद्दों पर राज्यों की आशंकाओं का समाधान किये बिना ही भारत सरकार ने 14 अप्रैल, 1994 ई0 को ळ।ज्ज पर हस्ताक्षर कर दिया। फलतः 1 जनवरी, 1995 ई0 को अस्तित्व में आये ँण्ज्ण्व् का भारत संस्थापक सदस्य बन गया। वैश्विकरण की प्रक्रिया से जुड़ने के कुछ वर्ष बाद ही भारतीय संघ के राज्यों में इसको लेकर एक अनौपचारिक आम सहमति कायम हो गयी तथा सभी राज्यों ने इससे जुड़े लाभों तथा अवसरों का दोहन करने के लिए अपनी नीतियों तथा योजनाओं में व्यापक परिवर्तन करना शुरू कर दिया। वैश्वीकरण के कारण भारतीय संघवादी व्यस्था में केन्द्र की भूमिका में स्पष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। जहाँ केन्द्र सरकार पहले बाजार की हर गतिविधियों में हस्तक्षेप करती थी, अब वह बाजार के सन्दर्भ में प्रबन्धकीय भूमिका निर्वाह कर रही है।

आज प्रत्येक क्षेत्र में वैश्वीकरण का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण 'क्षेत्रवाद एवं तद्जनित समस्याएँ' भी सामने आ रही है। विकसित देश वैश्वीकरण में मानवाधिकार, लोकतंत्र, निःशस्त्रीकरण, आतंकवाद, उन्मूलन को भी शामिल करने का प्रयास कर रहे है। विकसित देश विकासशील देशों में मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे है। मानवाधिकार संगठन रिपोर्ट 2000 के अनुसार मानवाधिकार का सर्वाधिक उल्लंघन अमेरिका जैसे विकसित देशों में हो रहा है। निःशस्त्रीकरण लोकतंत्र के नाम पर भी विकासशील देशों में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अमेरिका का ईराक पर हमला 2003 ई0 इसका एक सामाजिक उदाहरण है। वैश्वीकरण के उपरोक्त सभी पहलुओं से विकासशील देशों की सम्प्रभुता सीमित हो रही है। यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों को लाभ होगा परन्तु लैटिन अमेरिकी देशों का अनुभव यह बताता है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप उनकी अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ा है। वैश्वीकरण के शोषण के फलस्वरूप लैटिन अमेरिकी देशों का राजनीतिक मानचित्र आज बदल चुका है। वहाँ के अधिकांश देशों में समाजवादी सरकारें स्थापित हो चुकी है जो वैश्वीकरण और वैश्वीकरण नीतियों का विरोध कर रहे है। वर्तमान में लैटिन अमेरिकी देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं का भी अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे है। ये देश मिलकर अपने सहयोगी बैंक का निर्माण कर रहे है। लैटिन अमेरिका के सात देशों अर्जेण्टीना, ब्राजील, बोलिबिया, इक्वाडोर, पराग्वे, उरूग्वे और वेनेजुएला ने मिलकर बैंकों डेलसूर की स्थापना की है। इस प्रकार विकासशील देश वैश्वीकरण को विकसित देशों को प्रभुत्व के रूप में देख रहे है।

भारत के आर्थिक विकास की गति को त्वरित करने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में दीर्घकालीन पूँजी निवेश करके अभूतपूर्व योगदान दिया है। विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु विश्व बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किये गये है। देश की परिवहन, संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढाँचा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण आदि दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

निष्कर्षतः हम कह सकते है कि वैश्वीकरण का एक चेहरा बेबस गरीब औरत का है, जो अपने भूखे बच्चों के लिए खामोश और उदास है तो दूसरी ओर उसके चेहरे पर पूरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति तीव्र आक्रोश है। विश्व के सभी देश अलग–अलग परिस्थितिवश सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक, आर्थिक जनसंख्या औद्योगीकरण, नगरीकरण, कृषि, संगीत, सैन्य आदि से जुड़े सभी पक्ष इत्यादि वैश्वीकरण के अधीन हो गये है जिससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम आसानी से सामना कर सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- द – दैनिक जागरण 07 अप्रैल, 2011, सम्पादकीय 'आर्थिक सुधारों के दो दशक' –गुरूचरण दास पृष्ठ–10
- द – अमीन समीन 'भूमण्डलीकरण के युग में पूँजीवाद' – अनुवादक (राम कवीन्द्र सिंह ग्रन्थ शिल्पी)
- द – पाण्डेय राम नरेश : 'विश्व व्यापार संगठन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था' – एटलांटिक पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली–2004
- द – इण्डिया टूडे, नवम्बर–2008
- द – कुरूक्षेत्र–मार्च–2012
- द – *'Globlization & Socio-Economic Development'- Hemant S. Ahluwallia*